

1. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में आज 30 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति : प्रदेश के लगभग 15 लाख शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा।
2. 9 फरवरी से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र : 11 फरवरी को पेश किया जायेगा बजट।
3. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025—26 किया पेश : चालू वित्त वर्ष में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7 दशमलव 4 प्रतिशत रहने का अनुमान। और
4. सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए समानता संबंधी नियमों पर लगाई रोक : प्रतिष्ठित न्यायविदों की समिति द्वारा नियमों की समीक्षा का दिया सुझाव।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 32 प्रस्ताव आए, जिनमें 30 को स्वीकृति मिली। बैठक में आगामो बजट सत्र को भी मंजूरी मिल गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के वित्त और संसदीय

कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा और 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बाइट.....

विधानसभा का बजट सत्र 9 तारीख से प्रारंभ होगा और 11 तारीख को बजट आएगा। 9 तारीख को महामहिम श्री राजपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद 10 तारीख को क्योंकि एक हमारे दो माननीय सदस्यों का निधन हो गया इसलिए उनके निधन पर श्री शोक व्यक्त किया जाएगा और 11 तारीख को 11रु00 बजट आएगा वर्ष 26-27 का।

प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को भी बड़ी राहत दी है। प्रदेश के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी और उनके आश्रित परिवार सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। इससे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होंगे।

इस पर समग्र रूप से लगभग 448 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रेसवार्ता में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना से बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 12 लाख शिक्षक व कर्मी लाभान्वित होंगे। बाइट.....

कुल मिलाकर के 11,95,391 हमारे जो प्रदेश में शिक्षक हैं, इनके लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसको आज माननीय मंत्री परिषद के द्वारा सहमति मिली है। इसमें एक

व्यवस्था यह जोड़ी गई है और इसका जो कुल लागत है, वह लागत भी आएगी इसमें 358.61 करोड़ की।

श्री सिंह ने बताया कि स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद योजना का लाभ मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दी गई, जबकि सीएम फेलोशिप वाले अभ्यर्थियों को राज्य लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। कैबिनेट ने पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी।

देश में वित्त वर्ष 2025–26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर सात दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026–27 में वृद्धि दर छह दशमलव आठ से सात दशमलव दो प्रतिशत के बीच रह सकती है। यह अनुमान आज संसद में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण में व्यक्त किया गया।.....

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025–26 में वृद्धि की मजबूत गति को बनाए रखा है। पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर सात दशमलव चार प्रतिशत रहने का

अनुमान है, जिसमें घरेलू मांग का महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का हाल का आर्थिक प्रदर्शन दर्शाता है कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है। अनुकूल मानसून परिस्थितियों के सहयोग से वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि तीन दशमलव एक प्रतिशत रहने का अनुमान है। औद्योगिक गतिविधियों में गति मजबूत बनी रहने की संभावना है, जिसे जीएसटी के युक्तिसंगत होने और मांग के अनुकूल स्थितियां बनने से बल मिलेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित कुल महंगाई दर घटकर एक दशमलव सात प्रतिशत रह गई है, सर्वेक्षण के अनुसार, मुद्रा स्फीति की स्थिति अनुकूल बने रहने का अनुमान है। आनंद और भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।

वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की अगली कार्यवाही अब पहली फरवरी रविवार को होगी। इस दिन केन्द्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण नौ मार्च से दो अप्रैल तक आयोजित होगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन नियम-2026 को स्थगित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं, जिन्हें सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा

नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ 2026 के विनियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने आदेश दिया कि इस बीच 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे।

ब्रेक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिये आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन ए0आई0आर0 डॉट जी0ओ0वी0 डॉट आई0एन0 पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

प्रदेश के स्टाम्प तथा पंजीयन राज्य मंत्री — रवींद्र जायसवाल ने आज लखनऊ में एक प्रेसवार्ता में बताया कि आगामी 1 फरवरी से संपत्ति पंजीकरण में आधार प्रमाणीकरण लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। बाइट.....

अभी 1 तारीख से उत्तर प्रदेश में हर रजिस्ट्री में आधार के बेस पर चेक किया जाएगा। उसके अंगूठा लगा करके हम क्रॉस चेक कराएंगे। उसके

क्रॉस चेक में जो आधार पर उसके पूरी डाटा है इकट्ठा उसका नाम, लोकेशन, उसका निशान सब कुछ उसमें आ जाएगा तब रजिस्ट्री हम लोग करेंगे।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान के तत्वावधान में आज गोरखपुर में दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के सदस्य अलकेश शर्मा ने सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करते हुए कहा कि ये तत्व समावेशी विकास को गति देने एवं भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

प्रदेश भर में तकनीक और डिजिटल पहलों के ज़रिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संपन्न किया जा रहा है। वहीं कानपुर नगर में प्रशासन एसआईआर को लेकर मतदाताओं की शिकायतों का लगातार निस्तारण कर रहा है। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। बाइट

64 हमारे जो पुराने पहले से एईआरओ है और हमारे ईआरओ यह सब सुनवाई कर रहे बूथ बांट के और इसके क्रम में करीब 180 जगहों पर हमारी सुनवाई चल रही है, जिसमें लोग पहुंचे हैं और लोगों ने अपने कागज भी सबमिट किए हैं। इसके क्रम में अब तक 35,000 लोगों को सुनवाई भी की जा चुकी है और जो डॉक्यूमेंट्स उनसे चाहे गए थे वह लोगों ने सबमिट किए हैं।

दो दिवसीय यात्रा पर आई थाईलैंड की महारानी चौखुन फ्रा सिनी नाथा फ़िलात कल्याणी ने आज भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल मुकुट बंधन चत्य की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। इस दौरान थाईलैंड के उपप्रधानमंत्री बोर्नवोर्नसाक उवाननो सहित 70 सदस्योय थाई प्रतिनिधि मंडल भी शामिल रहा।

प्रदेश भर में ठंड और कोहरे का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 1 फरवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान भी जताया गया है।

(समाप्त)